



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 14 अक्टूबर, 2009 / 22 आश्विन, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 14 अक्टूबर, 2009

संख्या 3-28/2009-ई0एल0एन0.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 100/हि0प्र0-वि0स0/2009(1) एवं संख्या 100/हि0प्र0-वि0स0/2009(2), दोनों दिनांक 14 अक्टूबर, 2009 तदनुसार 22 आश्विन, 1931 (शक) जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उप धारा (1) और धारा 30 और 56 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा के 2 स्थानों की पूर्ती के लिए 3-रोहडू तथा 36-जवाली सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचन के कार्यक्रम से सम्बन्धित है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जन-साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,
अनिल खाची,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

अधिसूचना

दिनांक: 14 अक्टूबर, 2009
 22 आश्विन, 1931(शक)

सं० 100/हि०प्र०-वि०स०/2009(1).—यतः, हिमाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा में, उस राज्य के 3—रोहडू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित, श्री वीरभद्र सिंह का स्थान, उनके त्याग—पत्र देने के परिणामस्वरूप 28 मई, 2009 को रिक्त हो गया है; और

2. यतः, इस प्रकार उत्पन्न रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप—निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग इसके द्वारा.—

(अ) हिमाचल प्रदेश राज्य में 3—रोहडू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 16 नवम्बर, 2009 (सोमवार) से पूर्व और उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार उस राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में.—

(क)	नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	21 अक्टूबर, 2009 (बुधवार)
(ख)	नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	22 अक्टूबर, 2009 (गुरुवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अन्तिम तारीख	24 अक्टूबर, 2009 (शनिवार)
(घ)	वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा,	7 नवम्बर, 2009 (शनिवार)
(ङ)	वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा	16 नवम्बर, 2009 (सोमवार)

नियत करता है; और

(इ) 8:00 बजे पूर्वाह्न से 5:00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
 तपस कुमार,
 प्रधान सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110 001

Dated: 14th October, 2009
22 Asvina, 1931 (Saka)

NOTIFICATION

No.100/HP-LA/2009(1).—WHEREAS, the seat of Shri Virbhadra Singh, in the Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh, elected from 3-Rohru Assembly Constituency, has become vacant on 28th May, 2009, by reason of his resignation, and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of section 150, and section 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby.—

(A) calls upon the said 3-Rohru Assembly Constituency in the State of Himachal Pradesh, to elect, before the 16th November, 2009 (Monday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) **appoints**, with respect to the said election,—

- (a) the 21st October, 2009 (Wednesday), as the last date for making nominations;
- (b) the 22nd October, 2009 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 24th October, 2009 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 7th November, 2009 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary be taken; and
- (e) the 16th November, 2009 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) fixes the hours from 8.00 A.M. to 5.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
TAPAS KUMAR
Principal Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001.

दिनांक: 14 अक्टूबर, 2009
22 आश्विन, 1931(शक)

अधिसूचना

सं० 100/हि०प्र०-वि०स०/2009(2).— यतः, हिमाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा में, उस राज्य के 36—जवाली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित, श्री राजन सुशान्त का स्थान, उनके त्याग—पत्र देने के परिणामस्वरूप 26 मई, 2009 को रिक्त हो गया है; और

2. यतः, इस प्रकार उत्पन्न रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप—निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग इसके द्वारा.—

(अ) हिमाचल प्रदेश राज्य में 36—जवाली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 16 नवम्बर, 2009 (सोमवार) से पूर्व और उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार उस राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में.—

(क)	नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	21 अक्टूबर, 2009 (बुधवार)
(ख)	नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	22 अक्टूबर, 2009 (गुरुवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अन्तिम तारीख	24 अक्टूबर, 2009 (शनिवार)
(घ)	वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा,	7 नवम्बर, 2009 (शनिवार)
(ङ)	वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा	16 नवम्बर, 2009 (सोमवार)

नियत करता है; और

(इ) 8:00 बजे पूर्वाह्न से 5:00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
तपस कुमार
प्रधान सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110 001

Dated: 14th October, 2009
22 Asvina, 1931 (Saka)

NOTIFICATION

No.100/HP-LA/2009(2).—WHEREAS, the seat of Shri Rajan Sushant, in the Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh, elected from 36-Jawali Assembly Constituency, has become vacant on 26th May, 2009, by reason of his resignation, and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of section 150, and section 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby.—

(A) calls upon the said 36-Jawali Assembly Constituency in the State of Himachal Pradesh, to elect, before the 16th November, 2009 (Monday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) **appoints**, with respect to the said election.—

- (a) the 21st October, 2009 (Wednesday), as the last date for making nominations;
- (b) the 22nd October, 2009 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 24th October, 2009 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 7th November, 2009 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary be taken; and
- (e) the 16th November, 2009 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) fixes the hours from 8.00 A.M. to 5.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
TAPAS KUMAR
Principal Secretary.

लोक निर्माण विभाग**अधिसूचना**

शिमला-2, 12 अक्टूबर, 2009

सं० पी०बी०डब्ल्यू० (बी०)एफ०—(5)234/2008.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव गौरा/139, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी में देलड खड्ड पुल के निर्माण हेतु निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (मध्य क्षेत्र) मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (मध्य क्षेत्र) मण्डी, के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (बीघा)
मण्डी	लडभडोल	गौरा/139	958/1	1-4-2
			कुल जोड़ किता-1	1-4-2

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव।

ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-171002, the 09th September, 2009*

No. EDN-C-B(2) 35/2006.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to frame the recruitment scheme for the appointment of Part Time Water Carriers in the schools of Education Department (Elementary & Higher Education Departments) as under with immediate effect.—

1. OBJECTIVES :—

- To provide part time water carriers in Himachal Pradesh Government Schools against vacancies or specifically created posts.
- To empower the PRIs further by decentralization and involving PRIs to the effective running of Govt. Schools.
- To provide an opportunity for the unemployed youth of the Himachal Pradesh to work in Govt. Schools of their villages located in or adjacent the jurisdiction of the Gram Panchayat/Urban Local Bodies and earn a decent honorarium as well.

2. MODE OF APPOINTMENT.—The appointment shall be made by the selection committee to be constituted by the Government in the Education Department as notified from time to time.

3. ELIGIBILITY CRITERIA.—Only such candidates will be eligible to apply for a post of Part Time Water Carrier, who are :—

- Citizen of India.
- Of a sound mind.
- Have never been involved in any act of criminal nature.
- Permanent resident of the village /Gram Panchayat/ Urban local body of the area, in which the school is located, where the vacancy of part time water carrier exist.
- The candidates belonging to such adjacent Gram Panchayats where there is no GSSS/GHS/GMS/GPS shall have the opportunity with him/her to apply for the post of Part Time Water Carrier falling vacant in the equivalent school situated in the adjacent Panchayats.

4. IDENTIFICATION OF VACANCIES.—The Deputy Director, Elementary/Higher Education will identify the schools which have the vacancies. The Part Time Water Carriers will be recruited for the Govt. schools so identified by the Deputy Director, Elementary/Higher Education and approved by the department and the Government.

5. ADVERTISEMENT/NOTIFICATION OF VACANCIES.—School wise and Gram Panchayat/ Urban local body wise notification of vacancies will be done by the Deputy Director, Elementary/Higher Education after obtaining the approval from the Government through the Directorate of Elementary/Higher Education. The President/ Chairperson of the Urban local body / Pradhan Gram Panchayat will call applications for the recruitment against the post of Part Time Water Carriers by advertising through the Panchayat/ Urban local body/school notice boards.

6. APPLICATIONS.—The Candidates will have to apply for appointment as Part Time Water Carriers on plane paper, to the Pradhan, Gram Panchayat/President/Chairperson of the Urban local body of the area in which the Govt. school is located alongwith photocopies of certificates, which shall be compared with the originals at the time of interview. The candidates are also required to paste one attested pass-port size photograph on the application form.

7. INTERVIEW AND MARKS:

- (i) The selection committee shall judge the suitability of the candidates purely on merit. The Member Secretary of the Committee will maintain complete record of the selection process.
- (ii) The selection committee shall hold interviews by calling all the eligible candidates.
- (iii) Preference will be given to candidates who are from families without any member in Government service.
- (iv) The selection will be purely specific to a particular school only.

- (v) In the interview marks shall be awarded to the candidates out of 30.

The distribution of marks shall as under:—

(1)	For candidates of village/ town at distance:	
(a)	Upto 1.5 Kms. from school	10 Marks
(b)	Upto 2 Kms. from school	08 Marks
(c)	Upto 3 Kms. from school	06 Marks
(d)	Upto 4 Kms. from school	04 Marks
(e)	Upto 5 Kms. from school	02 Marks
(2)	For candidates whose families have donated land for school.	05 Marks
(3)	Candidates belonging to SC/ST/OBC	03 Marks
(4)	Candidates belonging to unemployed families	05 Marks
(5)	Interview/ Viva	07 Marks
	TOTAL	30 Marks

8. APPLICATION OF RESERVATION ROSTER.—Since this is a contractual engagement by the Gram Panchayat/ Urban local bodies, for a particular school and that too for a specific period on a fixed remuneration, therefore, reservation roster is not applicable.

9. SELECTION PROCEDURE.—Candidates will be selected by a committee comprising of representatives of the PRIs/Urban local bodies and the Department.

10. ELIGIBILITY FOR APPLICATIONS.—The candidates with requisite educational and age qualifications should be permanent resident of the same village/ Panchayat/ Urban local body, in which the Govt. school is located, for which the vacancy has been notified.

- The candidates belonging to such adjacent Gram Panchayats where there is no GSSS/GHS/GMS/GPS shall have the opportunity with him/her to apply for the post of Part Time Water Carrier falling vacant in the equivalent school situated in the adjacent Panchayats.

11. SELECTION COMMITTEE.—As notified by the Government from time to time.

12. COMPASSIONATE GROUND APPOINTMENTS.—The Government will have the power to appoint any candidate as Part Time Water Carrier on compassionate grounds without following the selection process if the candidate is below the poverty line or has a low income certificate issued by the Naib Tehsildar, Tehsildar, SDO (C) or Executive Magistrate of the concerned area and if the candidates is a:—

- (i) widow; or
- (ii) woman deserted by her husband or otherwise destitute; or
- (iii) a handicapped person; or
- (iv) an orphan.

13. DECELERATION OF RESULT.—Based on all relevant certificates enclosed with the application, a merit list will be drawn up and the person at the top will be offered appointment within 15 days of the interview subject to the verification of all information and certificates against the originals.

14. APPOINTMENTS.—The appointment of the selected part time water carriers will be made on contractual basis by the employer Gram Panchayat/ Urban local body after executing a proper agreement between the candidate selected for appointment and the employer Gram Panchayat/Urban local body on the prescribed form of agreement at Annexure-1.

15. WAITING LIST.—For every selected candidate, a waiting list of two candidates will be prepared on merit. The waiting list will be valid for one year after the selection process is over. Waiting list candidates may be appointed if the selected candidate does not join or he/she leaves the job within one year of appointment.

16. WAGES / HONORARIUM.—The Part Time Water Carriers will be paid an honorarium of Rs. 1000/- per month of 10 months in an academic year, by the respective employer Gram Panchayat/ Urban local body of the area out of the Grant-in-Aid allocation made available by the State Government.

17. AGE.—As prescribed by the Government from time to time. The age limit is to be reckoned on the first day of the year in which the posts are advertised by the Gram Panchayats/Urban local body of the area. The relaxation in the upper age limit in r/o categories of SCs/STs/OBCs etc. will also be admissible as per the State Government norms.

18. APPOINTING/ PUNISHING AUTHORITY.—The Part Time Water Carriers so recruited shall be contractual employees of the Gram Panchayat/ Urban local body for all intents and proposes. The appointing/ punishing authority in respect of Part Time Water Carriers will be the employer Gram Panchayat/ Urban local body.

19. ADMISSIBILITY OF CASUAL OR ANY KIND OF LEAVE:

- (i) One casual leave will be admissible to the Part Time Water Carriers after putting in one month continuous service. Total casual leave admissible to the Part Time Water Carriers will not exceed ten in a year. No other kind of leave will be admissible to the Part Time Water Carriers.
- (ii) Continuous absence beyond one week from the school without approval of the employer shall automatically lead to the termination of the services of the part time water carriers. The part time water carriers will not be entitled for any wages/ honorarium for the period of absence.

20 RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT.—The Candidates appointed as Part Time Water Carriers under the scheme, by the respective Gram Panchayat/Urban local bodies of the areas in which the Govt. school is located shall have no RIGHT to claim regularization/ absorption/ appointment as regular class-IV employees of the State Government.

The Government of Himachal Pradesh shall have the right to relax/ amend any of the terms & conditions/ provisions mentioned in the above scheme in public interest.

21. Repeal & Savings:

- (i) The recruitment scheme for the appointment of Part Time Water Carriers in Education Department notified vide notification No. EDNC-B (2)-7/95 dated 6-7-1996 and in

Elementary Education Department notified vide notification No. EDN-C-B(2)-7/95 dated 27-7-2001 further amended vide notification No.EDN-C-B(2)-7/95-Loose dated 29.1.2005 and No. EDN.C.B.(2)-35/2006-Loose dated 12-09-2007 are hereby repealed.

- (ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under these schemes, so repealed shall be deemed to have been validly made, done or taken.

By order,
P.C. DHIMAN,
Pr. Secretary.

ANNEXURE-I

FORM OF AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN GRAM PANCHAYAT/URBAN LOCAL BODY AND PART TIME WATER CARRIERS SELECTED UNDER PART TIME WATER CARRIER SCHEME, 2009

An agreement made this the _____ day of _____ in the year _____ between _____ (hereinafter called 'the contractual worker of the FIRST PART' and the Pradhan Gram Panchayat/President/Chairperson Urban Local Body of the other part.)

Whereas the Gram Panchayat has engaged the party of the FIRST PART and the party of the FIRST PART has agreed to serve as part time water carrier on the terms and conditions hereinafter contained.

WHEREBY it is agreed as follows:

1. That the PART TIME WATER CARRIER shall remain in the service of the Govt. School/institution, village _____ Gram Panchayat _____ for a period commencing on the day of _____ and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of employment of a party of the FIRST PART shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day on _____. No formal notice /order by the party of the Second Part conveying the same shall be necessary.
2. That the employee shall submit himself/herself to the orders of the Gram Panchayat/Urban Local Body and of the officers and the authorities under whom he/she may from time to time to be placed by the Gram Panchayat/Urban Local Body and shall abide by the instruction issued by the Gram Panchayat/ Urban Local Body and the Education Department from time to time.
3. That he/she shall employ himself/herself efficiently and diligently and to the best of his/her ability as Part Time Water Carrier and that he/she shall devote his/her time to the duties of the service and shall not engage directly or indirectly in any trade/business or occupation on his/her own account and that he/she shall not (except in case of accident or sickness certified by civil surgeon/authorised medical officer) absent himself/herself from his/her

said duties without having obtained prior permission from the immediate officer. The Part Time Water Carriers will not be entitled for any remuneration for the period of absence.

4. The service of the party of the FIRST PART shall terminate as follows:—

- (i) Automatically at the end of term given in the appointment letter.
- (ii) By the Gram Panchayat/ Urban Local Body without previous notice, if the GRAM PANCHAYAT/URBAN LOCAL BODY is satisfied on medical evidence before it, that the party of the FIRST PART is unfit and is likely for a considerable period to continue unfit by reason of ill health for the discharge of his/her duties. Provided always that the decision of the GRAM PANCHAYAT/URBAN LOCAL BODY that the party of the FIRST PART is likely to continue unfit shall be conclusively binding on the party of the FIRST PART and thereupon his/her services shall be terminated.
- (iii) By the GRAM PANCHAYAT/ Urban Local Body or its officers having proper authority without any previous notice, if the party of the FIRST PART is on to be prima-facie guilty of any insubordination, intemperance moral turpitude or other misconduct or of any breach or non-performance of any of the provisions of these presents, or is otherwise found unsuitable for the efficient performance of his/her duties.
- (iv) By one-month notice in writing given at any time during services under this agreement either by the Part Time Water Carrier to the Gram Panchayat/Urban Local Body or by the competent authority to the Part Time Water Carriers.
- (v) Provided always that the GRAM PANCHAYAT/ URBAN LOCAL BODY may pay the Part Time Water Carriers, one-month's remuneration in lieu of such notice, and thereupon this agreement shall stand terminated forthwith.

5. GRAM PANCHAYAT/URBAN LOCAL BODY shall pay the Part Time Water Carriers as long as the employee shall remain on contract and actually performs the duties assigned to him/her, a consolidated remuneration of Rs. 1000/- per month. No other allowances shall be admissible.

6. In respect of any matter of which no provision has been made in this agreement, or in the Part Time Water Carrier Scheme, 2009, shall be dealt with as per the instructions issued by the Govt. from time to time.

7. The Part Time Water Carriers shall have to execute the work assigned to him/her by the competent authority, other than his/her own duties in public interest.

8. It is expressly stated and agreed to by the party of the FIRST PART that any duration of service under this agreement shall in no way give him/her any right to claim for absorption in regular vacancies that exist or may arise in future in particular cadre.

9. NOTWITHSTANDING anything herein before contained in this agreement the Govt. shall be free to make departure from the terms and conditions of this agreement in the exigencies of public service or in public interest if the circumstances so warrant.

10. This offer of appointment is non-governmental on a fixed remuneration and it does not entitle him/her for any governmental scale.

11. FIRST PARTY shall have to furnish a declaration to the effect that he/she has not more than one living spouse in case he/she is married.
12. FIRST PARTY will be required to take the prescribed oath of allegiance to the Constitution of India.
13. FIRST PARTY engagement is subject to character and antecedents being certified to be good by two gazetted officers responsible persons not being its relatives.
14. FIRST PARTY will have to furnish attested copies of certificates in support of date of birth, academic qualification etc. at the time of joining the contract.
15. FIRST PARTY will have to produce medical certificate of its fitness from a Govt. Medical Officer before joining.
16. No TA/DA will be paid to FIRST PARTY for joining the contract. IN WITNESS WHEREOF THE party of the FIRST PART and Pradhan Gram Panchayat/ President/Chairperson of Urban Local Body on behalf of the party of the OTHER PART have hereinto set their hands the day, month and year first, above written.

SIGNED BY:-

PARTY OF THE FIRST PART

IN THE PRESENCE OF;

1. _____

2. _____

SIGNED BY:-

PARTY OF THE SECOND PART

IN THE PRESENCE OF;

1. _____

2. _____

हिमाचल प्रदेश सरकार वन विभाग ।

संख्या एफ0एफ0ई0-बी0ई0(3) -43/2006-खण्ड-I तारीख शिमला-171002, 13 अक्टूबर, 2009

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 32 के खण्ड (एल) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रस्तावित नियम बनाती हैं और इन्हें एतद्वारा हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना हेतु प्रकाशित करती हैं;

इन नियमों के बाबत किसी (किन्हीं) हितबद्ध व्यक्ति (व्यक्तियों) को कोई आक्षेप करने या सुझाव देने हों तो वह (वे) उसे (उन्हें) इस अधिसूचना के राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से 21 दिन की अवधि के भीतर प्रधान मुख्य अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश को भेज सकता/सकते हैं;

नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप(पों) या सुझाव(वों), यदि कोई हो, तो उन्हें प्रधान मुख्य अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा अपनी संस्तुतियों/रिपोर्ट सहित प्रशासनिक विभाग को अग्रेषित किया जाएगा तथा प्रस्तावित प्रारूप नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

1 . संक्षिप्त नाम.- इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वन (अधिकार धारकों को ईमारती लकड़ी का वितरण) नियम, 2009 है।

2. परिभाषाएँ.-(1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) 'सरकार' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

- (ख) पद 'गरीबी रेखा से नीचे' का वही अर्थ होगा जो इसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग द्वारा समनुदेशित है;
- (ग) 'अधिकार धारक' से अधिकार अभिलेख में सम्बन्धित क्षेत्र की वन बन्दोबस्त रिपोर्ट के अनुसार अभिलिखित अधिकारों का प्रयोग करने के लिए हकदार व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (घ) 'अधिकार अभिलेख' से वन बन्दोबस्त रिपोर्टों में अभिलिखित अधिकार अभिप्रेत हैं;
- (ङ) 'ईमारती लकड़ी वितरण' से वन बन्दोबस्त रिपोर्टों में अभिलिखित अधिकार-अभिलेख के अनुसार अधिकार धारकों को ईमारती लकड़ी के वितरण की नीति (पालिसी) अभिप्रेत है; और
- (च) 'ईमारती लकड़ी' वितरण अधिकार से अधिकार धारक जिसके पास कृषि योग्य भूमि है, को सम्बन्धित क्षेत्र की वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में अभिलिखित अधिकार धारक के वास्तविक घरेलू उपयोग हेतु आवासिक मकान एवं गौशाला आदि के निर्माण हेतु ईमारती लकड़ी मंजूर (प्रदान) करने के अधिकार अभिप्रेत हैं।

(2) अन्य समस्त शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 में उनके हैं।

3. हकदारी.- ईमारती लकड़ी, उन अधिकार धारकों, जिनके वास्तविक घरेलू उपयोग हेतु आवासिक मकान, गौशाला इत्यादि के निर्माण/रखरखाव के लिए ईमारती लकड़ी वितरण को मंजूर (प्रदान) करने के लिए सम्बन्धित वन बन्दोबस्त रिपोर्टों में अभिलिखित अधिकार हैं, को मंजूर की जाएगी:-
परन्तु यह कि:-

- (i) शहरी क्षेत्रों में ईमारती लकड़ी का वितरण मंजूर नहीं किया जाएगा;
- (ii) यदि सम्बन्धित अधिकार धारक की निजी (प्राइवेट) भू-धृति पर आवासिक मकान, गौशाला आदि के निर्माण की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए वृक्ष उपलब्ध हो तो, सम्बन्धित अधिकार धारक को कोई ईमारती लकड़ी का वितरण मंजूर नहीं किया जाएगा। तथापि, उसे हिमाचल प्रदेश भू-परिरक्षण अधिनियम, 1978 और तद्विनिर्माण बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार अपनी निजी भूमि से वृक्षों को गिराने (काटने) का अधिकार होगा;

- (iii) यदि अधिकार धारक ने अपनी निजी (प्राइवेट) भू-धृति में से वृक्षों का विक्रय किया है तो उसे दस वर्ष तक कोई ईमारती लकड़ी का वितरण मंजूर नहीं किया जाएगा;
- (iv) यदि अधिकार धारक (बर्तनदार) की एक से अधिक स्थानों पर भू-धृति हो तो उसे केवल एक स्थान पर ही ईमारती लकड़ी का वितरण (टी0डी0) लेने का विकल्प होगा। इस प्रयोजन के लिए अधिकार धारक एक शपथ पत्र, जिसमें विभिन्न स्थानों पर उसके ईमारती लकड़ी वितरण (टी0डी0) अधिकारों तथा उस स्थान जहां उसने ईमारती लकड़ी वितरण (टी0डी0) प्राप्त करने का विकल्प चुना है स्पष्ट करते हुए, प्रस्तुत करेगा। विकल्प का प्रयोग एक बार कर लिया गया हो तो उसे परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;
- (v) इन नियमों के अधिसूचित होने की तिथि से ऐसे भू-स्वामियों को जिन्होंने अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के अधीन सरकार से अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् भूमि क्रय की हो, कोई ईमारती लकड़ी का वितरण मंजूर नहीं किया जाएगा, ऐसा भूमि के क्रय की तिथि को लिहाज में न रखते हुए किया जाएगा;
- (vi) ईमारती लकड़ी का वितरण केवल परिवार के मुखिया को ही राजस्व अभिलेख के अनुसार स्वीकृत किया जाएगा;
- (vii) वाणिज्यिक और भाड़े के प्रयोजनों हेतु उपयोग में लाये जाने वाले भवनों के निर्माण/रखरखाव के लिए ईमारती लकड़ी का वितरण मंजूर नहीं किया जाएगा;
- (viii) अधिकार धारकों को ईमारती लकड़ी का वितरण नहीं किया जाएगा यदि उस वन जहाँ पर सम्बन्धित अधिकार धारको का ईमारती लकड़ी वितरण अधिकार हो, में प्रयोजन हेतु वृक्ष वन वर्धकीय रूप में (सिल्वीकल्चरली) उपलब्ध न हो;
- (ix) अधिकार धारकों का ईमारती लकड़ी वितरण का अधिकार, वन संरक्षण में उनके सहयोग और सहभागिता के अध्यधीन होगा। यदि कोई अधिकार-

धारक अपराधियों को पकड़ने, आग बुझाने के कार्य में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असफल रहता है या वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में यथा अन्तर्विष्ट कोई वन अपराध करता है तो उसका ईमारती लकड़ी वितरण का अधिकार दस वर्ष तक के लिए निलम्बित कर दिया जाएगा;

- (x) यदि कोई अधिकार धारक ईमारती लकड़ी वितरण मंजूरी का दुरुपयोग करता हुआ पाया जाता है या दोबारा ईमारती लकड़ी वितरण हेतु पात्र बनने के पश्चात् कोई वन अपराध करता है तो उसके ईमारती लकड़ी वितरण अधिकार को 10 वर्ष तक के लिए निलम्बित कर दिया जाएगा।

4. परिमाण (मात्रा).- (1) अधिकार धारकों को अलग से विनिर्दिष्ट किए जाने वाले डिपुओं से, निम्न नियत मापदण्डों पर ईमारती लकड़ी का वितरण, संपरिवर्तित रूप में, स्वीकृत किया जाएगा :-

- (i) नये आवास के निर्माण हेतु = 3 घनमीटर ; और
(ii) अनुरक्षण हेतु = 1 घनमीटर

(2) ईमारती लकड़ी का वितरण नाश रक्षित (सालवेज) (गिरे हुए, सूखे खड़े) में से वन वर्धकीय रूप में (सिल्वीकल्चरली) उपलब्ध हरे वृक्षों में से वरीयता के अनुसार दी जाएगी।

5. नियतकालिकता.- अधिकार धारकों को ईमारती लकड़ी वितरण (टी0डी0) स्वीकृत करने की नियतकालिकता (समयावधि) इस प्रकार होगी :-

- (i) नए भवन निर्माण के लिये जीवन में एक बार या तीस वर्ष, जो भी पश्चात वर्ती हो ;
- (ii) परिवर्धन/परिवर्तन के लिये पन्द्रह वर्ष में एक बार; और
- (iii) नए प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों/अग्नि पीड़ितों के लिए : वास्तविक आवश्यकता (अपेक्षा) के अनुसार उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) द्वारा की गई सिफारिश पर और संबद्ध सहायक अरण्यपाल/वन मण्डल अधिकारी द्वारा

व्यक्तिगत सत्यापन के पश्चात् नियम 4 के अधीन विहित अधिकतम मात्रा से अनधिक की मंजूरी के अध्वधीन।

6. **दरें .-** विभिन्न अधिकार धारकों को ईमारती लकड़ी के वितरण की मंजूरी हेतु प्रभारित की जाने वाली दरें निम्न प्रकार से होंगी :-

(i) गरीबी रेखा से ऊपर के अधिकार-धारक को:

उन दरों का 30% जिनपर हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित (लिमिटेड) द्वारा वाणिज्यिक तौर पर ईमारती लकड़ी की बिक्री की गई है;

(ii) गरीबी रेखा से नीचे के अधिकार धारक को:

उन दरों का 10% जिनपर हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित (लिमिटेड) द्वारा वाणिज्यिक तौर पर ईमारती लकड़ी की बिक्री की गई है

(iii) प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित अधिकार-धारक को: निशुल्क।

7. **ईमारती लकड़ी वितरण की मंजूरी हेतु प्राथमिकता.-** ईमारती लकड़ी वितरण की मंजूरी हेतु गरीबी रेखा से नीचे के अधिकार-धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी। गरीबी रेखा से ऊपर के अधिकार-धारकों को ईमारती लकड़ी वितरण की मंजूरी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी।

8. **ईमारती लकड़ी वितरण मंजूरी की प्रक्रिया.-** ईमारती लकड़ी वितरण की मंजूरी हेतु आवेदन, इन नियमों से उपाबन्ध-1 के रूप में संलग्न प्रारूप में अधिकार-धारकों द्वारा सम्बन्धित पटवारी से आवश्यक टिप्पण (रिमार्क) प्राप्त करने के पश्चात्, सम्बन्धित पंचायत को प्रस्तुत किया जाएगा। पंचायत अधिकार-धारकों की आवश्यकता (अपेक्षा) की असलीयत का अभिनिश्चयन करने के पश्चात्, सम्बन्धित व्यक्ति(यों) के ईमारती लकड़ी के वितरण की आवश्यकता (अपेक्षा) के वास्तविक परिमाण (मात्रा) को उपदर्शित करते हुए प्रस्ताव पारित करेगी। सम्बन्धित पंचायत द्वारा ईमारती लकड़ी के वितरण की मंजूरी की सिफारिश का प्रस्ताव पारित करने के पश्चात् अधिकार-धारक अपनी ईमारती लकड़ी के वितरण हेतु आवेदन क्षेत्र के वन रक्षक (गार्ड) को प्रस्तुत करेगा, जो, इसे, इस प्रयोजन के लिए रखे रिजिस्टर में दर्ज करेगा और आवेदन की पावती अधिकार धारक को जारी करेगा। वह माँग

की असलीयत का अभिनिश्चयन करने के पश्चात् अपनी सिफारिशों को खण्ड अधिकारी को भेजेगा, जो अपनी सिफारिशों को वन परिक्षेत्र अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। वन परिक्षेत्र अधिकारी से ईमारती लकड़ी वितरण हेतु आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् वन मण्डल अधिकारी, स्वयं, माँग की असलीयत और सम्बन्धित वन में वृक्षों/ईमारती लकड़ी की वनवर्धित (सिल्वीकल्चरली) उपलब्धता का समाधान होने पर ईमारती लकड़ी वितरण की मंजूरी हेतु कार्रवाई करेगा और इन नियमों से उपाबन्ध-11 के रूप में संलग्न प्रारूप पर सम्बन्धित अधिकार-धारक को ईमारती लकड़ी वितरण की मंजूरी के बारे अपना विनिश्चय सूचित करेगा। वन मण्डल अधिकारी द्वारा ईमारती लकड़ी वितरण मंजूरी हेतु एक अनुसूची बनाई जाएगी और उसे वन मण्डल की समस्त पंचायतों और अन्य कृत्यकारियों को प्रचार हेतु अधिसूचित किया जाएगा।

9. **ईमारती लकड़ी के वितरण की मंजूरी हेतु समय अनुसूची.-** अधिकार धारक ईमारती लकड़ी के वितरण की मंजूरी हेतु सम्बन्धित वन रक्षक को सम्बन्धित पंचायत के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 31 मई तक आवेदन करेंगे। नियम 8 के अधीन प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पर कार्रवाई (प्रोसैस) की जाएगी और पात्र अधिकार धारकों को उस वर्ष के अक्टूबर और दिसम्बर के मध्य ईमारती लकड़ी का वितरण किया जाएगा और तत्पश्चात् उस वर्ष के लिए ईमारती लकड़ी का वितरण मंजूर नहीं किया जाएगा।
10. **ईमारती लकड़ी वितरण के उपयोग के लिए अधिकारिता:-** इन नियमों के अधीन मंजूर ईमारती लकड़ी वितरण हैम्बर लगाने के पश्चात् ईमारती लकड़ी को किसी भी अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना, राजस्व सम्पदा के भीतर ले जाने की अनुमति होगी, और यदि ईमारती लकड़ी को एक सम्पदा से दूसरी सम्पदा में ले जाना हो, तो, अधिकार धारक को इस प्रयोजन हेतु सम्बन्धित वन परिक्षेत्र अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी। अधिकार-धारक द्वारा मंजूर ईमारती लकड़ी का उपयोग अधिकतम एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा। यदि मंजूर ईमारती लकड़ी वितरण का उपयोग विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जा सके, तो सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी मामले की असलीयत के आधार पर इसके उपयोग हेतु समयावधि के विस्तारण की मंजूरी देगा। वन मण्डल अधिकारी अपने कर्मचारिवृन्द के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि मंजूर ईमारती लकड़ी वितरण का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया गया है जिसके लिए वह मंजूर की गई थी। यदि मंजूर ईमारती लकड़ी वितरण का अनुज्ञेय अवधि के दौरान उपयोग नहीं किया गया है

तो उसे वन विभाग द्वारा जब्त किया जा सकेगा और वन मण्डल अधिकारी द्वारा ईमारती लकड़ी वितरण की मंजूरी के सम्बन्ध में लिया गया विनिश्चय अन्तिम होगा।

11. **डिपो.-** उन डिपुओं जहाँ से अधिकार धारकों को ईमारती लकड़ी का वितरण परिवर्तित रूप में किया जाएगा को प्रत्येक वर्ष वन मण्डल अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। आगामी वर्ष के दौरान इन डिपुओं के स्थान परिवर्तन को भी अधिसूचित किया जाएगा। इन अधिसूचनाओं को वन मण्डल अधिकारी द्वारा पंचायत स्तर तक व्यापक रूप में परिचालित किया जाएगा।
12. **वितरित की जाने वाली ईमारती लकड़ी का आकार और आयाम (लम्बाई-चौड़ाई)**
.- वितरित की जाने वाली ईमारती लकड़ी को हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु तैयार किये जाने वाले मानक आकारों से भिन्न, विभिन्न आकारों में परिवर्तित और विक्रय किया जाएगा।
13. **आंकड़ा संचय (डाटा वेस) की मानीटरिंग और निरीक्षण.-** अधिकार धारकों के ब्यौरा, अधिकार धारकों द्वारा प्रयोग किये गए विकल्पों, लकड़ी वितरण की मंजूरी आदि से सम्बन्धित आंकड़े सम्बन्धित पंचायत द्वारा और रेंज (परिक्षेत्र) वार वन मण्डल अधिकारी द्वारा अनुरक्षित और मानीटर किए जाएंगे। यह डाटा (आंकड़ा) मुख्य अरण्यपाल वन (मानीटर एवं मूल्यांकन) द्वारा सुन्दरनगर में पुनश्च मानीटर और मूल्यांकित किया जाएगा और वार्षिक रिपोर्ट प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन हिमाचल प्रदेश को भेजी जाएगी।
14. **शास्ति एवं दण्ड.-** अधिकार धारक जो,-
 - (i) वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु ईमारती लकड़ी वितरण का दुरुपयोग करते हैं ;
 - (ii) वितरित की गई ईमारती लकड़ी (टी0डी0) का विक्रय करते हैं ;
 - (iii) अनुज्ञा के बिना राजस्व सम्पदा की अधिकारिता से बाहर ईमारती लकड़ी का परिवहन करते हैं ;
 - (iv) परमिट (अनुज्ञा पत्र) में दी गई समय अनुसूची के अवसान के पश्चात् वितरित की गई ईमारती लकड़ी (टी0डी0) का उपयोग करते हैं ;

- (v) वन बन्दोबस्त रिपोर्ट उल्लिखित कर्तव्यों का, अधिकारों सहित, सहित निर्वहन नहीं करते हैं ;

को सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी द्वारा यथा अवधारित ऐसी अवधि हेतु उनके अधिकारों के निलम्बन के अतिरिक्त, भारतीय वन अधिनियम, 1927 के सुसंगत उपबन्धों के अनुसार दण्डित किया जाएगा।

15. निरसन एवं व्यावृत्तियाँ.-

- (1) सरकार या हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा, अधिकार धारकों (बर्तनदारों) के लिए ईमारती लकड़ी वितरण सम्बन्धी बनाए एवं जारी किए गए विद्यमान नियमों, अधिसूचनाओं, निर्देशों एवं अनुदेशों का एतद्वारा निरसन किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन या विखण्डन के होते हुए भी ऐसे निरसित नियमों और इस प्रकार विखण्डित अधिसूचनाओं, निर्देशों और अनुदेशों तत्स्थानी के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उपाबन्ध-।

प्ररूप

(नियम-8 देखें)

ईमारती लकड़ी वितरण की स्वीकृति हेतु आवेदन के लिए प्रपत्र

- | | | |
|----|---------------------------------------|-------|
| 1. | आवेदक का नाम | _____ |
| 2. | व्यवसाय | _____ |
| 3. | पिता का नाम | _____ |
| 4. | परिवार के सदस्यों की संख्या | _____ |
| 5. | क्या आवेदक परिवार का मुखिया(कर्ता) है | _____ |
| 6. | गाँव | _____ |
| 7. | डाकघर | _____ |
| 8. | तहसील | _____ |

9. जिला _____
10. पंचायत _____
11. क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से सम्बन्धित है। यदि हाँ, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
12. वर्ष जिसमें टी0डी0 पहले दी गई थी और मंजूर की गई टी0डी0 की मात्रा/ वृक्षों की संख्या _____
13. प्रयोजन जिसके लिए टी0डी0 अपेक्षित है। _____
(चाहे वह नये आवासीय मकान/ गौशाला बनाने के लिए या मुरम्मत के लिए) _____
14. अपेक्षित टी0डी0 का ब्यौरा

प्रजाति	घनमीटर में मात्रा	जंगल का नाम जिसमें अधिकार दर्ज है।

15. मैं एतद द्वारा यह घोषणा करता हूँ :-

- i) टी0डी0 की आवश्यकता शहरी क्षेत्र में निर्माण/मुरम्मत के लिए नहीं है।
- ii) मकान/गौशाला के निर्माण/मुरम्मत की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वृक्ष मेरी भूमि पर उपलब्ध नहीं है।
- iii) मैंने पिछले 10 वर्षों में अपनी भूमि से 10 वर्षीय पातन कार्यक्रम के अन्तर्गत मैंने किन्हीं भी वृक्षों का विक्रय नहीं किया है।
- iv) मेरी भूमि केवल एक स्थान/एक से अधिक स्थानों पर अर्थात् _____ स्थान पर टी0डी0 प्राप्त करने हेतु शपथ पत्र वन मण्डल अधिकारी को दिया जा चुका है/संलग्न है।
- v) मैं मूल अधिकार धारक हूँ और परिवार का मुखिया भी हूँ।
- vi) मैंने हिमाचल प्रदेश अभिवृत्ति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के अधीन सरकार की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् भूमि क्रय नहीं की है।

- vii) मैं, घर के निर्माण/मुरम्मत के प्रयोजन के लिए मुझे प्रदान की गई टी0डी0 का उपयोग, वाणिज्यिक/किराए के प्रयोजन के लिए नहीं करूंगा।
- viii) मैं समझता हूँ कि टी0डी0 अधिकारों सहित अधिकार तथा रियायतें वन संरक्षण में अधिकार धारकों के सहयोग और सहभागिता के अध्वधीन है तथा मैं वन अपराधियों को पकड़ने, आग बुझाने इत्यादि हेतु अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा, और
- ix) मैं टी0डी0 ग्रांट का दुरुपयोग नहीं करूंगा और वन विभाग के इस सम्बन्ध में बनाए गए नियमों/अनुदेशों का पालन करूंगा।

तारीख: _____

(आवेदक के हस्ताक्षर)

बड़े अक्षरों में नाम _____

पंचायत का सत्यापन/रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि श्री _____ सपुत्र श्री _____ गांव _____ मौजा _____ का स्थाई निवासी है तथा परिवार का मुखिया है। आवेदक की लकड़ी की अपेक्षा वास्तविक है और उसे _____ घनमीटर लकड़ी घर/गौशाला के निर्माण/मुरम्मत के लिए अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न है।

तारीख: _____

प्रधान ग्राम पंचायक की मुहर

एवं हस्ताक्षर ।

पटवारी की रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि श्री _____ सपुत्र श्री _____ गांव _____ मौजा _____ का स्थाई निवासी है। आवेदक कृषि योग्य भूमि खसरा नं0 _____ रकबा का मालिक है और _____ रुपये सालाना भू0 राजस्व के रूप में अदा करता है और उसके टी0डी0 में पेड़ प्राप्त करने के अधिकार हैं। वह परिवार का मुखिया है।

तारीख _____

हल्का पटवारी के हस्ताक्षर

वन रक्षक की रिपोर्ट

- i) आवेदक ने पिछले 30 वर्षों में नए आवासीय घर/गौशाला के निर्माण के लिए टी0डी0 के अन्तर्गत अपने जीवनकाल में पेड़ प्राप्त नहीं किये हैं/आवेदक ने पिछले

15 वर्षों में आवासीय घर/गौशाला की मुरम्मत के लिए टी0डी0 के अन्तर्गत टी0डी0 प्राप्त नहीं की है।

- ii) आवेदक ने 10 वर्षीय पातन कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले 10 वर्षों में अपनी जमीन से कोई पेड़ नहीं बेचे हैं।
- iii) आवेदक की अपनी निजी भूमि में खड़े पेड़ नहीं है।
- iv) आवेदक ने वन सम्पदा को कोई हानि/क्षति नहीं पहुँचाई है/वन भूमि पर अवैध कब्जा नहीं किया है और आवेदक के विरुद्ध वन अपराध के बारे में कोई क्षतिपूर्ति रिपोर्ट/प्राथमिकि सूचना/न्यायालय मामला (कोर्ट केस) आदि लम्बित नहीं है।
- v) ईमारती लकड़ी की अपेक्षा _____ कार्य के लिए है।
- vi) आवेदक वन संरक्षण में पूर्ण सहयोग देता है।
- vii) आवेदक को _____ घनमीटर परिवर्तित लकड़ी _____ डिपू से मंजूर (स्वीकृत) की जाये।
- viii) टी0डी0 में मंजूरी के लिए संस्तुत पेड़/टिम्बर उस वन में वन वर्धकीय रूप में (सिल्वीकल्चरली) उपलब्ध है जहाँ पर अधिकार-धारक के टी0डी0 अधिकार हैं।

तारीख: _____

वन रक्षक के हस्ताक्षर
बीट _____

वन खण्ड अधिकारी (ब्लॉक आफिसर) की रिपोर्ट

- i) प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में दिये गए तथ्य (कथन) एवम् वन रक्षक द्वारा दिये गए प्रमाण पत्र सही हैं।
- ii) मैंने नए आवासीय घर/गौशाला के निर्माण स्थल/आवासीय घर/गौशाला की मुरम्मत स्थल जहाँ पर टी0डी0 का प्रयोग प्रस्तावित है, का दौरा/निरीक्षण किया है एवं वन का भी दौरा/निरीक्षण किया है और आवेदक को _____ प्रजाति की _____ घनमीटर लकड़ी स्वीकृत कर दी जाए जो कि उस वन में वन वर्धकीय रूप में (सिल्वीकल्चरली) उपलब्ध है।

वन खण्ड अधिकारी (ब्लॉक आफिसर)
के हस्ताक्षर
वन खण्ड _____

तारीख: _____

वन पक्षिेत्र अधिकारी की रिपोर्ट

आवेदक की आवश्यकता वास्तविक है और उसे _____ प्रजाति की _____ घनमीटर लकड़ी _____ डिपू से मंजूर (स्वीकृत) की जाए, जिसके लिए पेड़ वनवर्धकीय रूप में (सिल्वीकल्चरली) उपलब्ध हैं।

तारीख: _____

हस्ताक्षर _____
वन परिक्षेत्र अधिकारी _____वन मण्डल अधिकारी द्वारा स्वीकृति

आवेदक को एतद्वारा _____ प्रजाति की _____ घनमीटर
लकड़ी _____ डिपो से स्वीकृत की जाती है।

तारीख: _____

हस्ताक्षर _____
वन मण्डल अधिकारी _____
_____ वन मण्डल।अनुबन्ध-IIप्ररूप

(नियम-8 देखें)

संख्या:
हिमाचल प्रदेश वन विभाग।

प्रेषक

वन मण्डल अधिकारी,
_____ वन मण्डल,

प्रेषित

श्री/श्रीमति _____
गांव _____ डाकघर _____
तहसील _____ जिला _____ हि० प्र०

तारीख _____

विषय: टी0डी0 मंजूर (प्रदान) करने बारे ।

श्री मान जी,

आपके आवेदन पत्र तारीख _____ के सन्दर्भ में ।

2. आपके घर/गौशाला के निर्माण/मुरम्मत के लिए _____ प्रजाति की _____ घनमीटर लकड़ी प्राप्त करने बारे प्राप्त आवेदन पत्र पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा विचार किया गया व निर्णय लिया गया है कि :-

घर/गौशाला के निर्माण/मुरम्मत के लिए _____ प्रजाति की _____ घनमीटर लकड़ी _____ डिपो से मंजूर की जाए। डिपो से लकड़ी मंजूरी की तारीख से _____ मास के भीतर उठाई जाएगी और _____ मास के भीतर या समय बढौतरी के भीतर यदि कोई हो, प्रयोग की जाएगी अन्यथा आपके द्वारा टी0डी0 में प्राप्त लकड़ी जब्त किए जाने हेतु दायी होगी।

अथवा

आपके टी0डी0 आवेदन-पत्र पर विचार किया गया और निम्नलिखित आधारों पर रद्द कर दिया गया :-

भवदीय,

वन मण्डल अधिकारी,
_____ वन मण्डल ।

पृष्ठांकन संख्या _____ तारीख _____

प्रतिलिपि वन राजिक _____ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

वन मण्डल अधिकारी,
_____ वन मण्डल,

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

[Authoritative English Text of this Department notification number FFE-B-E(3)-43/2006-Vol-I dated 13th October, 2009 as required under clause (3) of article 348 of the constitution of India]

FOREST DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 13th October, 2009

No. FFE-B-E(3)-43/2006-Vol-I.—In exercise of the powers conferred by clause (L) of Section 32 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following rules and the same are hereby published in the Rajpatra of Himachal Pradesh for the information of the persons likely to be effected thereby;

If any interested person(s) has/have any objection(s) or suggestion(s) with regard to these rules, he/she/they may send the same to the Principal Chief Conservator of Forests, Himachal Pradesh within a period of 21 days from the date of publication of this notification;

Objection(s) or suggestion(s), if any, received within stipulated period shall be forwarded to the Administrative Department by the Principal Chief Conservator of Forests, Himachal Pradesh with his recommendations/report which shall be considered by the Government before finalizing the proposed draft rules; namely :-

1. Short title.—These rules shall be called the Himachal Pradesh Forest (Timber Distribution to the Right Holders) Rules, 2009.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires.—

- (a) ‘Government’ means the Government of Himachal Pradesh;
- (b) The term ‘below poverty line’ shall have meaning as assigned to it by the Department of Panchayati Raj, Himachal Pradesh;
- (c) ‘Right Holder’ means a person entitled to exercise rights recorded in the ‘record of rights’ as per the Forest Settlement Report of the area concerned;
- (d) ‘Record of rights’ means, rights recorded in the Forest Settlement Reports;
- (e) ‘Timber Distribution’ means the policy of distribution of timber to the right holders as per record of rights recorded in the Forest Settlement Reports; and
- (f) ‘Timber Distribution Rights’ means right of a Right Holder having cultivable lands for grant of timber for construction of residential house and cow shed etc. for bonafide domestic use of the Right Holder, recorded in the Forest Settlement Report of the area concerned;

(2) All other words and expressions used but not defined in these rules shall have the meaning assigned to them in the Indian Forest Act, 1927.

3. Entitlement.—Timber shall be granted to the Right Holders who have their recorded rights in the concerned Forest Settlement Reports for grant of Timber Distribution for construction/maintenance of residential house, cow sheds etc. for bonafide domestic use:

Provided that:—

- (i) no Timber Distribution shall be granted in urban area;
- (ii) no Timber Distribution shall be granted if trees to meet the requirement of timber for construction of residential house, cowshed etc. are available on the land holdings of the Right Holder concerned. However, he shall have the right to fell trees from his own land as per the provisions of the Himachal Pradesh Land Preservation Act, 1978 and rules made there under;
- (iii) no Timber Distribution shall be granted for 10 years if the right holder has sold trees from his private land holding;
- (iv) in case right holder has land holding at more than one place, he shall have option of getting Timber Distribution at one place only. For this purpose a Right Holder shall submit an affidavit clarifying therein his rights of Timber Distribution at different places and his place of option for getting Timber Distribution. Option once exercised shall not be allowed to be changed;
- (v) With effect from the date of notification of these Rules, no Timber Distribution shall be granted to a land owner who has purchased land after obtaining the permission of the Government under section 118 of the Tenancy and Land Reforms Act, 1972, irrespective of the date of purchase of such land.
- (vi) Timber Distribution shall be granted only to the head of the family as per the revenue records;
- (vii) Timber Distribution shall not be granted for the construction/ maintenance of buildings to be used for commercial and hiring purposes;
- (viii) Timber Distribution shall not be granted to the Right Holders, if trees for the purpose are not available silviculturally in the forest where concerned right holders have Timber Distribution right;
- (ix) Timber Distribution Rights shall be subject to cooperation and participation of Right Holders in forest conservancy. In case any Right Holder fails to perform his duties for apprehending offenders, extinguishing fire or commits any forest offence as contained in the Forest Settlement Report, his right of Timber Distribution shall be suspended upto 10 years; and
- (x) Timber Distribution Right of a Right Holder shall be suspended upto 10 years if he is found to have mis-utilized the Timber Distribution grant or committed any forest offence after he becomes eligible again for Timber Distribution.

4. Quantity.—(1) Timber Distribution shall be granted in converted form from the depots to be specified separately as per scale fixed below.—

- (i) for construction of new house = 3 cubic meters; and
- (ii) for maintenance = 1 cubic meter.

(2) Timber Distribution shall be given from salvage (fallen, dry standing), silviculturally available green trees in the order of preference.

5. Periodicity.—The periodicity for grant of Timber Distribution to the Right Holders will be as under.—

- (i) for new construction once in life time or 30 years whichever is later;
- (ii) for additions/alterations – once in 15 years; and
- (iii) sufferers of natural calamities/fire sufferers: as per actual requirement as recommended by the Sub Divisional Officer (Civil) and after personal verification by the ACF/DFO concerned subject to the grant not exceeding the maximum limit prescribed under rule-4.

6. Rates.—The rates to be charged from the different types of Right Holders for grant of Timber Distribution will be as under.—

- (i) Right Holders above poverty line- 30% of the rates at which timber is sold by the Himachal Pradesh State Forest Development Corporation Ltd. commercially;
- (ii) Right Holders below poverty line- 10% of the rates at which timber is sold by the Himachal Pradesh State Forest Development Corporation Ltd. Commercially; and
- (iii) Right Holders suffering from natural calamities- Free of cost.

7. Priority for grant of Timber Distribution.— Priority for grant of Timber Distribution shall be given to the Right Holders belonging to Below Poverty Line. Right Holders above poverty line shall be granted Timber Distribution on first come first served basis.

8. Procedure for grant of Timber Distribution.—Application for grant of Timber Distribution, on the form appended to these rules as 'Annexure-I' shall be submitted by Right Holder (s) to the Panchayat concerned after getting necessary remarks from the patwari concerned. The Panchayat after ascertaining genuineness of the requirement of the Right Holders shall pass resolution indicating actual quantity of requirement of Timber Distribution of the individual (s) concerned. After resolution recommending grant of Timber Distribution is passed by the concerned panchayat, right holders shall submit his Timber Distribution application to the Forest Guard of the area who shall enter the same in the register maintained for the purpose and issue receipt of the application to the Right Holder. He shall send his recommendations to the Block Officer after ascertaining the genuineness of demand, who in turn shall submit his recommendations to the Range Officer. After receipt of Timber Distribution application from the Range Officer, the Divisional Forest Officer shall take action for sanction of the Timber Distribution after satisfying himself about the genuineness of the requirement and silvicultural availability of trees/timber in the concerned forest and intimate his decision/ Timber Distribution grant to the Right Holder concerned on the proforma appended to these rules as 'Annexure II'. A schedule for grant of Timber Distribution shall be framed and notified for publicity to all panchayats and other functionaries in the Forest Division by the Divisional Forest Officer.

9. Time schedule for grant of Timber Distribution.—The right holders shall apply for grant of Timber Distribution through concerned Panchayat to the concerned forest guard by 31st May of each year. The application shall be processed and Timber Distribution shall be given to eligible right holders between October and December of the year as per procedure under rule 8 and no Timber Distribution shall be granted thereafter for that year.

10. Jurisdiction of the use of Timber.—Timber granted under these rules shall be allowed to be carried within revenue estate without obtaining any permission after affixing of

Timber Distribution hammer and if the timber is to be carried out from one estate to another, the Right Holder shall have to obtain a permission from the Range Officer concerned for this purpose. Timber granted shall be utilized by the Right Holder within a period of maximum one year. In case, Timber Distribution grant could not be utilized within the specified period, concerned Divisional Forest Officer shall grant extension for its use based on the genuineness of the case. The Divisional Forest Officer shall ensure through his staff that the Timber Distribution grant is used for the purpose for which it was sanctioned. In case Timber Distribution grant is not utilized during the permissible period, the same may be seized by the Forest Department and the decision taken by the Divisional Forest Officer relating to grant of Timber Distribution shall be final.

11. Depot.—The depots from where Timber Distribution in converted form shall be supplied to the right holders shall be notified by the Divisional Forest Officer every year. Any change during the next year in the place of these depots shall also be notified. These notifications shall be widely circulated up to the Panchayat level by the Divisional Forest Officer.

12. Size and dimensions of Timber Distribution timber.—The Timber Distribution timber shall be converted and sold in different sizes other than standard sizes made by Himachal Pradesh State Forest Development Corporation Ltd for commercial purpose.

13. Monitoring of data base and checking.—The data regarding details of right holders, options exercised by the right holders, Timber Distribution granted, utilized, etc. shall be maintained and monitored panchayat and range wise by the Divisional Forest Officer concerned. This data shall further be monitored and evaluated by Chief Conservator of Forests (Monitoring and Evaluation) at Sundernagar and annual report sent to Principal Chief Conservator of Forests, Himachal Pradesh.

14. Penalty and Punishment.—The right holders who,—

- (i) misuse of Timber Distribution for commercial purpose;
- (ii) sells Timber Distribution;
- (iii) transports timber outside the jurisdiction of Revenue estate without permission;
- (iv) utilizes Timber Distribution after the time schedule given in permit has expired; and
- (v) do not participate in the duties enshrined in the Forest Settlement Report alongwith rights,
shall be penalized as per relevant provisions of Indian Forest Act, 1927, in addition to suspension of their rights for such period as may be determined by the concerned Divisional Forest Officer.

15. Repeals and savings.—(1) The existing rules, notifications, directions and instructions framed and issued by the Government or Himachal Pradesh Forest Department concerning the Timber Distribution to the Right Holders are hereby repealed and rescinded.

(2) Notwithstanding such repeal or recession any action taken or anything done under the rules so repealed and notifications, directions and instructions framed and issued so rescinded shall be deemed to have been taken or done under the corresponding provisions of these rules.

FORM

(See rule-8)

ANNEXURE-I

PROFORMA FOR APPLICATION FOR GRANT OF TIMBER DISTRIBUTION

1. Name of Applicant. _____
2. Occupation _____
3. Father's Name _____
4. No. of family members _____
5. Is the applicant head of family _____
6. Village. _____
7. Post Office _____
8. Tehsil _____
9. District _____
10. Panchayat _____
11. Whether the applicant belongs to _____
'below poverty line' family. If yes,
enclose attested copy of certificate
issued by the competent Authority.
12. Year in which Timber Distribution _____
was earlier granted and quantity/No.
of trees granted.
13. Purpose for which Timber Distribution required _____
(whether for new construction of residential
house/cowshed or for maintenance)
14. Details of Timber Distribution required :

Specie	Volume in Cubic metre	Name of forest where right exists

15. I, hereby declare that,—

- (i) Timber Distribution requirement is not for construction/maintenance of house located in urban area;

- (ii) trees to meet the requirement for construction/maintenance of house/cowshed are not available on my land;
- (iii) I have not sold any trees from my land under the 10 year felling programme during the last 10 years;
- (iv) I have land holding at only one place/more than one place i.e. at _____.
An affidavit regarding my option for getting Timber Distribution at _____
has been submitted to the Divisional Forest Officer, _____/enclosed
herewith;
- (v) I am the original right holder and also the head of the family;
- (vi) I have not purchased land after obtaining the permission of the Government under Section 118 of the Tenancy and Land Reforms Act, 1972;
- (vii) I shall not use timber granted to me for the purpose of construction/maintenance of house to be used for commercial/hiring purposes;
- (viii) I understand that rights and concessions including Timber Distribution rights are subject to cooperation and participation of right holders in forest conservancy and I shall perform my duties for apprehending forest offenders, extinguishing fire etc. and
ix) I shall not misuse the Timber Distribution grant and abide by the rules/instructions of the Forest Department in this regard.

(Signature of applicant)

Dated _____

Name in block letters _____

Verification/report of Panchayat :

It is certified that Sh. _____ S/o Sh. _____ is a permanent resident of village _____ Mauza _____ and is head of the family. The requirement of timber of the applicant is genuine and he requires _____ Cum of timber for construction/maintenance of his house/cowshed. A copy of resolution passed by the Panchayat in this regard is enclosed.

Dated _____

Seal & Signature of
Pradhan Gram Panchayat**Report of Patwari :**

Certified that Sh. _____ S/o Sh. _____ is a permanent resident of _____ Mauza _____. Applicant is owner of the cultivable land comprising Khasra number _____ measuring _____ and pays _____ amount of Rs. _____ per annum as land Revenue and has a right to obtain trees in T.D. He is the head of the family.

Dated _____

Signature Halqua Patwari

Report of Forest Guard:

- (i) The applicant has not obtained timber under Timber Distribution for construction of new residential house/cowshed during his life time/for the last 30 years/the applicant has not obtained timber under Timber Distribution for maintenance of residential house/cow shed for the last 15 years.
- (ii) Applicant has not sold any trees from his land during the last ten years under 10 years felling programme.
- (iii) Applicant does not have trees standing on his own private land.
- (iv) The applicant has not caused any loss/damage to forest wealth/encroached forest land and no damage report/FIR/court case relating to any forest offence is pending against him.
- (v) The requirement of timber is on account of _____.
- (vi) The applicant extends full cooperation in protection of the forest.
- (vii) The applicant may be sanctioned _____ cum converted timber of _____ species from _____ depot.
- (viii) Timber recommended for grant in Timber Distribution are silviculturally available in the forest where right of the right holder exists.

Signature
Forest Guard

_____ Beat

Report of Block Officer (Deputy Ranger):

- (i) Certified that the contents of the application and the certificates given by the beat Guard are correct.
- (ii) I have visited and inspected the site of construction of new residential house/cow shed/maintenance of residential house/cow shed, where Timber Distribution grant is proposed to be utilized and also the forest on spot and the applicant may be granted _____ Cum of timber of _____ species in converted form which is silviculturally available from _____ forest.

Signature
Block Officer, _____ Block

Report of Range Officer:

The requirement of the applicant is genuine and he may be granted _____ Cum timber of _____ species from the _____ Depot for which trees are silviculturally available.

Signature _____
Forest Range Officer _____

Sanction by DFO :

_____ Cum of timber of _____ species from _____ Depot is hereby granted to the applicant.

Signature
Divisional Forest Officer,
_____ Forest Division.

FORM
(See rule-8)
Annexure-II

No.
Himachal Pradesh Forest Department

From

Divisional Forest Officer,
_____ Forest Division,

To

Sh/Smt _____
Village _____ Post Office _____
Tehsil _____ Distt. _____
Dated _____

Subject:— Grant of Timber Distribution

Sir,

Please refer to your application dated _____.

2. Your application for grant of _____ cum timber of _____ species for construction/maintenance of house/cowshed has been considered by the undersigned and it is decided

to sanction TD measuring _____(cum) of _____ species from _____ Depot for the construction/maintenance of house/cowshed. The timber shall be lifted from the depot within _____ months from the date of sanction and shall be utilized within _____ months or within the extension granted, if any, otherwise the timber obtained by you in T.D. is liable to be seized.

OR

that your TD application has been considered and rejected on the following grounds.—

Yours faithfully,
Sd/-
Divisional Forest Officer,
_____ Forest Division.

Endst. No.

Dated

Copy forwarded to Range Officer _____ for information and necessary action.

Divisional Forest Officer,
_____ Forest Division,

By order,
Sd/-
Addl. Chief Secretary.

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), चच्योट स्थित गोहर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री मुनी लाल पुत्र श्री खीमा राम, निवासी गांव व डा0 चच्योट, तहसील चच्योट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी ।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मुनी लाल पुत्र श्री खीमा राम, निवासी गांव व डा0 चच्योट, तहसील चच्योट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी ताई का नाम श्रीमती काली देवी है जिनकी मृत्यु 12-12-1991 को हुई है। अज्ञानतावश वह अपनी ताई का नाम मृत्यु रजिस्टर ग्राम पंचायत चच्योट के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सका। जिसे दर्ज करने के आदेश पारित किए जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु पंचायत रिकार्ड में कटवाने बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 6-11-2009 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असातन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
चच्योट स्थित गोहर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), चच्योट स्थित गोहर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री देविन्द्र कुमार पुत्र श्रीमती सुमित्रा देवी, निवासी सलाहर, डा0 देवधार, तहसील चच्योट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी।

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री देविन्द्र कुमार पुत्र श्रीमती सुमित्रा देवी, निवासी सलाहर, डा0 देवधार, तहसील चच्योट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना—पत्र दिया है कि उसका नाम देविन्द्र कुमार है तथा जन्म तिथि 2—3—1985 है। अज्ञानतावश उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत मझोटी देवधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जिसे दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म तिथि व नाम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 6—11—2009 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असातन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 5—10—2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
चच्योट स्थित गोहर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री भूरि सिंह पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव कटलग, डा0 पधियुं, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) वर्तमान समय में इस कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत द्वारा इस कार्यालय को एक प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि प्रार्थी ने अपना नाम भूरि सिंह से बदल कर राजवीर रख लिया है तथा भविष्य में उसे इसी नाम से जाना जाए।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी को उक्त नाम के बदलने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर/एतराज इस नोटिस के प्रकाशन के एक माह के भीतर इस कार्यालय में हाजर आकर दर्ज करवा सकता है अन्यथा उक्त नाम को बदलने बारे नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 8—10—2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक आयुक्त,
उपायुक्त, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री आशिष कोहली, उप मण्डल दण्डाधिकारी, शिमला शहरी, तहसील व जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश

श्रीमती प्रबल कुमारी चौहान पत्नी श्री विजय कुमार चौहान, निवासी व डा0 भद्रवाड़, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त नाम दुरुस्त करने बारा में।

श्रीमती प्रबल कुमारी चौहान पत्नी श्री विजय कुमार चौहान, निवासी व डा0 भद्रवाड़, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन-पत्र दिया है कि उसका नाम शादी से पहले प्रबल ठाकुर रिकार्ड में दर्ज था परन्तु शादी के बाद प्रबल कुमारी चौहान हो गया है। प्रार्थिया अपने नाम को सर्विस रिकार्ड में दुरुस्त करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि जिसको भी उक्त प्रार्थिया के नाम प्रबल ठाकुर के बजाए प्रबल कुमारी चौहान सर्विस रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे आपत्ति है तो वह अपने आरोप दिनांक 14-11-2009 तक या उससे पहले कार्यालय में हाजिर आकर पेश कर सकता है।

आज दिनांक 14-10-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

आशिष कोहली,
उप मण्डल दण्डाधिकारी,
शिमला शहरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री रजनेश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, भू-व्यवस्था, वृत्त अर्की, जिला सोलन,
हिमाचल प्रदेश

बाद संख्या 4, 5, 8, 9/आफ 2008

मुकद्दमा : तकसीम आराजी।

श्री राम लाल पुत्र श्री जीवणू गांव कुईरु सहरोल, परगना सन्धूर्त शर्की, तहसील अर्की, जिला सोलन,
हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

श्री अमर सिंह आदि निवासी कुईरु सहरोल, परगना सन्धूर्त शर्की, तहसील अर्की, जिला सोलन,
हिमाचल प्रदेश . . प्रत्यार्थीगण।

तकसीम अराजी बावत खाता खतौनी नं0 87/94 कित्ता 13 रकबा तादादी 81-4 बिघा व आराजी खाता/खतौनी नम्बर 82/89 कित्ता 2 रकबा 7-3 बिघा वाक्या मौजा कुईरु सहरोल, आराजी खाता/खतौनी नम्बर 25/25 खसरा नम्बर 2 रकबा 2-7 बिघा वाक्या मौजा सहलाना व आराजी खाता/खतौती नम्बर 7/7 खसरा नम्बर 20 रकबा 0-4 बिस्वा वाक्या, मौजा कल्याणपुर, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रत्यार्थी राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्ण, निवासी कुईरु सहरोल को अदालत द्वारा असालतन समन किए गए परन्तु प्रत्यार्थी को तामील असालतन नहीं हो रही है। जिससे अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रत्यार्थी को तामील असालतन नहीं हो सकती है।

अतः इस इशतहार के द्वारा प्रत्यार्थी को सूचित किया जाता है कि उक्त मुकद्दमा में तारीक पेशी दिनांक 4-12-2009 निश्चित की है। अतः आप निश्चित तारीक पर उपस्थित आकर मुकद्दमा की पैरवी स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से करें अन्यथा आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 5-10-2009 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

रजनेश कुमार,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, भू-व्यवस्था,
वृत्त अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला.-2, 13 अक्टूबर, 2009

संख्या एफ0एफ0ई0बी-एफ(3)-1/94-लूज.—यतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मौजा बालीचौकी, उप तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश के निरीक्षण गृह व वन रक्षक गृह तथा अन्य भवन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निदिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों तथा श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत; अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप मण्डलाधिकारी (नागरिक) गोहर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला मण्डी

उप तहसील

बालीचौकी

गांव	खसरा नम्बर	बीघा	विश्वा	विश्वांसी
बालीचौकी	504	0	1	0
उप तहसील बालचौकी	505	0	1	5
जिला मण्डी (हि0प्र0)	506	0	5	2
किता	3	0	7	7

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित / —
अतिरिक्त मुख्य सचिव।